



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022020-216085  
CG-DL-E-11022020-216085

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 41]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941
No. 41]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

---

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

मामला सं. एसएसआर 02/2020

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लोट ग्लास" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

**फा. सं. 07/02/2020-डीजीटीआर.—**1. मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि., मैसर्स सिसकेम फ्लेट ग्लास इंडिया लि., मैसर्स गोल्ड प्लस ग्रास इंडस्ट्री लि. और मैसर्स असही इंडिया ग्लास लि. (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "क्लीयर तथा टिंटेड वैरायटी (ग्रीन ग्लास को छोड़कर) के 2 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर मोटाई के फ्लोट ग्लास (दोनों मोटाई सहित), परंतु उनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा स्वचालित प्रयोजनों के लिए बने रिफ्लैक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं हैं" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" (पीयूसी) भी कहा गया है) के

आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदकों ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आरोप लगाया है और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने तथा निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।

### **पृष्ठभूमि**

3. चीन जन.गण.और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/12002-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा 22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा चीन जन.गण.और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर 12 नवंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
4. प्राधिकारी द्वारा प्रथम निर्णायक समीक्षा 13 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/01/2007-डीजीएडी द्वारा की गई थी और प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम चीन जन.गण.और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए 2 दिसंबर, 2008 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/01/2007-डीजीएडी द्वारा जारी किये गये थे। चीन जन.गण.और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2009-सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित किया गया था जो 22 मई, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2009-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित किया गया था।
5. प्राधिकारी ने केवल चीन जन. गण. के विरुद्ध 3 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा दूसरी निर्णायक समीक्षा की गई थी और प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम चीन जन.गण.और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए 2 जुलाई, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा जारी किये गये थे। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया। चीन जन.गण.से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना केंद्र सरकार द्वारा 8 सितंबर, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित किया गया था। वर्तमान शुल्क 7 सितंबर, 2020 तक लागू है।

### **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

6. वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में तथा बाद की निर्णायक समीक्षा जांचों में परिभाषित किये गये अनुसार, "क्लीयर तथा टिंटेड वैरायटी (ग्रीन ग्लास को छोड़कर) के 2 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर मोटाई के फ्लोट ग्लास (दोनों मोटाई सहित), परंतु उनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा स्वचालित प्रयोजनों के लिए बने रिफ्लैक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं हैं" है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 08 सितंबर, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क द्वारा विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से "रिफ्लैक्टिव ग्लास" को अलग किया गया था।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में "ग्लास एंड ग्लासवेयर" श्रेणी के तहत तथा सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार 7005 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध सामान जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता, पाटित आयातों के प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोगों तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और, इसीलिए, नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान चीन जन. गण. से आयात किये जा रहे विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माने जा रहे हैं।

### घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि., मैसर्स सिसकेम फ्लेट ग्लास इंडिया लि., मैसर्स गोल्ड प्लस ग्रास इंडस्ट्री लि. और मैसर्स असही इंडिया ग्लास लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किये गये अनुसार उनका हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 88 प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक उद्योग मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. ने चीन जन. गण. से आंतरिक गुणवत्ता और परीक्षण उद्देश्य के लिए स्वल्प मात्रा (अपनी विक्री का 0.2 प्रतिशत से कम) में संबद्ध सामान का आयात किया है। मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. द्वारा आयातों की छोटी सी मात्रा पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. को नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग माना है। अन्य किसी भी आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक चीन जन. गण. के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदक नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में अंतर्निहित प्रावधानों की शर्तों में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया है।

### पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आधार

10. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए क्योंकि चीन जन. गण. को डीजीटीआर सहित विश्व भर के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चूंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल की जांचों में चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है और इसीलिए उसे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, घरेलू उद्योग ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में जर्मनी का सुझाव दिया है। जर्मनी को प्रतिनिधि देश के रूप में प्रस्तावित करते समय घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. और जर्मनी, दोनों निर्यात केंद्रित हैं और उनकी प्रभावी घरेलू मांग अतिरिक्त उत्पादन को नहीं खपा सकती। इसके अतिरिक्त, जर्मनी संबद्ध सामानों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। जर्मनी संबद्ध सामानों का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अतः स्थानीय खपत, प्रतिस्पर्धा, निर्यातानुसूखता आदि के संदर्भ में फ्लोट ग्लास के विकास का स्तर व्यापक रूप से समान है। चूंकि, आवेदक जर्मनी में विद्यमान कीमतों को प्राप्त नहीं करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने जर्मनी में आयात कीमतों (स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप) के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। वही इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए विचार किये जाने का प्रस्ताव है। जर्मनी को प्रतिनिधि देश चीन जन. गण. के लिए अथवा किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था देश पर विचार करने के संबंध में अंतिम निर्णय इस जांच प्रक्रिया के दौरान सभी हितवद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।
11. आवेदकों ने वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और पत्तन सार संभाल व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, वैट समायोजन और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजन किये गये हैं।
12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आकलनों पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन चीन जन. गण. के लिए इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। परिणामी पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी तथा न्यूनतम सीमाओं से अधिक है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि चीन जन. गण. ने संबद्ध सामानों का प्रस्तावित सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है जो यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर निर्यात किये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. में

उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता तथा क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये आंकड़े भी और इस प्रकार जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पाटन की निरंतर संभावना भी दर्शाते हैं।

### **क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा कारणात्मक सम्बन्ध**

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और मात्रात्मक प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को क्षति अर्थात् तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग तथा बिक्री, उत्पादन में गिरावट और मालसूची में वृद्धि तथा बिक्री कीमतों में गिरावट से परिलक्षित कीमत प्रभाव के कारण सकारात्मक कीमत न्यूनीकरण, जांच की अवधि में हानियों और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय (आरओसीई) के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। उपर्युक्त तथ्य पाटन और क्षति जारी रहने के भी संकेतक हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता तथा क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये आंकड़े भी पाटनरोधी शुल्क बंद किये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना दर्शाते हैं।

### **निर्णायक समीक्षा की शुरुआत**

14. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पूर्ण लिखित आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि विद्यमान शुल्कों की समामि से पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, जांच की शुरुआत करते हैं।

### **शामिल देश**

15. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

### **जांच की अवधि**

16. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 (12 माह) है। हालांकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 (9 महीने) तक की जांच की अवधि (पीओआई) पर विचार करना उचित पाया है। क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि और जांच की अवधि को कवर करेगी।

### **प्रक्रिया**

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में केवल चीन जन. गण. के संबंध में 2 जुलाई, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के सभी पहलू शामिल हैं।
18. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध सामानों से संबंधित ज्ञात भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित तरीके एवं स्वरूप में पूर्ण संगत सूचना दायर कर सकें।

20. कोई भी अन्य हितवद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।
21. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किये जाएं:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001**

### **समय-सीमा**

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त पाठनरोधी नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
23. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

24. कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाला अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षा है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने के स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:
- i. गोपनीय चिह्नित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)
  - ii. अगोपनीय के रूप में चिह्नित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।
26. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए। इस प्रकार के चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितवद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।
27. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह

अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

28. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
29. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
30. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

32. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

#### **असहयोग**

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2020

Case No. SSR 02/2020

**Subject: Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of 'Float Glass' originating in or exported from China PR.**

**F. No. 07/02/2020-DGTR .—1.** M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd, & M/s. Asahi India Glass Ltd., (hereinafter also referred to as "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on

behalf of the Domestic Industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) from China PR (herein after also referred to as subject country).

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from China PR and consequent injury to the Domestic Industry and have requested for sunset review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from China PR.

### **Background**

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from the China PR and Indonesia was initiated by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 05<sup>th</sup> July, 2002. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 14/19/2002-DGAD dated 22<sup>nd</sup> August, 2003, recommending imposition of definitive duties. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 165/2003-Customs dated 12<sup>th</sup> November, 2003 on the import of the subject goods, originating in or exported from the China PR and Indonesia.
4. The first Sunset Review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/01/2007-DGAD dated 13<sup>th</sup> December 2007 and the final findings recommending continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR and Indonesia was issued by the Authority vide final findings Notification No. 15/01/2007-DGAD dated 02<sup>nd</sup> December 2008. The continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR and Indonesia was notified by the Central Government vide Custom's Notification No.04/2009-Customs dated 06<sup>th</sup> January 2009, amended by Custom's Notification No.51/2009-Customs dated 22<sup>nd</sup> May 2009.
5. The Authority initiated 2nd sunset-review investigation vide Notification No.15/24/2013-DGAD dated 3rd January 2014 against China PR and Indonesia, and the final findings recommending continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR was issued by the Authority vide final findings Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 2nd July 2015. The Designated Authority also recommended withdrawal of anti-dumping duty against Indonesia. The continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the China PR was notified by the Central Government vide Custom's Notification No.47/2015-Customs (ADD) dated 8<sup>th</sup> September, 2015. The current duties are applicable up-to 7<sup>th</sup> September 2020.

### **Product Under Consideration and Like Article**

6. The product under consideration in the present application, as defined in the original investigation as well as the in the subsequent sunset review investigations, is "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes". The Authority notes that "reflective glass" was excluded from the definition of the product under consideration by Customs Notification No. 47/2015-Customs dated 8<sup>th</sup> September 2015.
7. The product under consideration is classified under the category ““Glass and Glassware” in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
8. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the Domestic Industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced

subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicants. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Domestic Industry in India are being treated as 'Like Article' to the product under consideration being imported from China PR.

#### **Domestic Industry**

9. The application for the sunset review has been filed by M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd, & M/s. Asahi India Glass Ltd., on behalf of the domestic industry. As claimed by Applicants, their share account for around 88% of the total domestic production. It is also noted that one of the applicant industries namely M/S Saint Gobain India Pvt. Ltd., has imported the subject goods of meagre quantity (less than 0.2% of their sales) from China PR for internal quality and testing purpose. Considering the small volume of imports by the M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd, the Authority has considered M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). None of the other Applicants has imported the subject goods from China PR. The Applicants have claimed not to be related to any importers or exporters from China PR. In view thereof, Applicants constitute the domestic industry within the meaning of the Rules. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

#### **Basis of likelihood of continuation or recurrence of Dumping**

10. The Applicants have claimed that China PR should be treated as non-market economy country, as China PR has been considered as a non-market economy country by various authorities world over including the Designated Authority. The Applicants have also claimed that since the Designated Authority has considered China PR as a non-market economy in the recent investigations, and therefore, it needs to be considered as non-market economy in terms of paragraph 8 (2) of Annexure I of the Rules. In this context, the Domestic Industry suggested Germany as an appropriate market economy third country for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. While proposing Germany as surrogate country, Domestic Industry has submitted that both China PR and Germany are export-centric and their effective domestic demand cannot absorb the excess production. Further, Germany is the fourth largest exporter of the subject goods. Germany is the second largest producer, after China, of the subject goods. Therefore, the level of development of Float Glass in terms of local consumption, competition, export-orientation, etc. is largely similar. Since the Applicants were not able to get the prevailing prices in Germany, they have claimed normal value for China PR, based on import prices in Germany (source: ITC Trade Map). The same is proposed to be considered for the purpose of this initiation. A final decision regarding consideration of Germany or any other market economy country as the surrogate country for China PR will be taken after receiving comments from all interested parties during the course of the investigation.
11. The Applicants have claimed export prices on the basis of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance and port handling expenses, inland freight, VAT adjustment and credit cost.
12. Considering the estimates of normal value and export price, dumping margin has been determined for the purpose of this initiation for China PR. The resultant dumping margin is positive and significant and much above de-minimis limit. There is prima facie evidence that the proposed normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the net export price, indicating that the subject goods originating in or exported from China PR are being exported at dumped prices. Further, the data provided by the petitioner on the capacity and export orientation of producers/exporters in China PR, also prima facie indicates the continued likelihood of dumping so as to justify the initiation of the investigation.



**Likelihood of continuation or recurrence of Injury and Casual Link**

13. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of volume effect i.e. decline in production, sales and capacity utilization as compared to immediately preceding year and increase in inventory and due to price effect as reflected from the decline in selling prices, positive price suppression, losses in POI and negative return on capital employed (ROCE). The above facts are indicative of continuation of injury to domestic industry. Further, the data provided by the Applicants on the capacity and export orientation of producers/exporters in China PR also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury to the Domestic Industry in the event of cessation of the anti-dumping duties.

**Initiation of Sunset Review**

14. In view of the duly substantiated written application by the Domestic Industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry, and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of existing duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

**Countries involved**

15. The country involved in the subject investigation is China PR.

**Period of Investigation**

16. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1<sup>st</sup> October 2018 to 30<sup>th</sup> September 2019 (12 months). However, The injury period shall cover the periods 1<sup>st</sup> April 2016 to 31<sup>st</sup> March 2017, 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018, 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019 and the period of investigation.

**Procedure**

17. The present sunset review covers all aspects of the final findings related to sunset review investigation issued vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 2<sup>nd</sup> July 2015, in respect of China PR.
18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Submission of Information**

19. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority  
Directorate General of Trade Remedies  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street  
New Delhi-110001

**Time Limit**

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices / Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

### **Inspection of Public File**

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

### **Non-cooperation**

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA Add. Secy. and Designated Authority